

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 6 अगस्त 2026 गुरुवार

सम्पादकीय

बड़े सपने और घटिया निर्माण

लखनऊ—कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटा था और उस उत्सव इस 63 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिबेटेड कॉरिडोर की तुलना अपनी की सड़कों से की गई थी। 4,200 करोड़ रुपये की इस परियोजना का सपना बड़ा था, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक निकली। उद्घाटन के महज तेरह दिन बाद उन्नाव जिले के कोरासी के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा कई मीटर तक धंस गया। एनएचएआई ने इसे 'सिलपेज की समस्या' और नियमित रखरखाव का हिस्सा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, मगर चार दिन बाद ही यही सड़क दोबारा धंस गई। जुलाई खत्म होते-होते यह सिलसिला कभी से कम पांच बार दोहराया जा चुका था। जिस सड़क को देश के सबसे महंगे टोल वाले एक्सप्रेसवे के रूप में पेश किया गया, वह हल्की बारिश भी नहीं झेल पाई। सवाल यह नहीं कि बारिश कितनी थी, बल्कि यह कि जो सड़क सामान्य मानसून के पहले ही ड्राइव में उखड़ जाए, उसकी नींव में आखिर डाला क्या गया था। यह अकेला उदाहरण नहीं है। इसी साल मई के आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक निर्माणधीन पुल का हिस्सा तेज तुफान के दौरान ढह गया था, जिसमें कम से कम छह मजदूरों की जान बली गई थी। जुलाई के मध्य में देहरादून-पांवटा साहिब मार्ग पर टैंस नदी पर बना सोलह करोड़ रुपये का पुल, जिस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुए मुश्किल से एक दिन बीता था, पहली बड़ी बारिश में ही जगह-जगह धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह पुल पहले भी एक बार ढह चुकी अस्थायी पुलिया की जगह जल्दबाजी में बनाया गया था। जून के आखिर में असम में एक पुल पूरी तरह बह गया, और गांव वालों ने बताया कि उन्होंने निर्माण के समय लोहे के बजाय पक्के कंक्रीट के पुल की मांग की थी, जिसे अनुसूचा कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि नदी पार स्कूल जाने वाले बच्चों और खेतों तक पहुंचने वाले किसानों का रास्ता भी बंद हो गया।

यह पैटर्न किसी एक राज्य या किसी एक ठेकेदार तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश के निर्माण तंत्र की बीमारी बन चुका है। संसद में हाल ही में केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया कि इस समय देश भर में 1,191 नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माणधीन हैं, जिनमें से 629 यानी करीब आधी परियोजनाएं तय समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकीं। इतना ही नहीं, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच घटिया गुणवत्ता के काम को लेकर 103 ठेकेदारों के खिलाफ गंडाबाड़ी की जा चुकी है। यह आंकड़ा खुद बता देता है कि निर्माण में कार्रवाई कोई इक्का-दुक्का घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। इसी दौर में हुए दुर्घटना विरेलपेज के आधार पर देश भर में 6,358 ऐसे सड़क हिस्सों को ब्लैक कोरिडोर के रूप में चिह्नित किया गया है, जहां बार-बार हादसे होते हैं। यानी जिन सड़कों को सुरक्षित और टिकाऊ बताकर जनता के पैसे से बनाया गया, उनमें से हजारों हिस्से खुद खारेज की निशानी बन चुके हैं। सवाल यह भी उठता है कि जब गुणवत्ता की जांच और ठेकेदारों पर कार्रवाई का तंत्र मौजूद है, तो फिर हर मानसून में यही कहानी क्यों दोहराई जाती है। जवाब निर्माण से जुड़े हर व्यक्ति को पता है, मगर खुलकर कोई नहीं बोलता। जहां भी नियामक का दोषी ठेकेदार भी काली सूची में डाले जाने के बाद नाया और कंपनी का घाटा बदलकर भाग सिर से टेडर बनने लगते हैं। घटिया निर्माण के दांभी ठेकेदार भी काली सूची में डाले जाने के बाद नाया और कंपनी का घाटा बदलकर भाग सिर से टेडर बनने लगते हैं। यह खेत डलना पुराना और इतना संगठित हो चुका है कि अब इसे रोकने वाला कोई डर बाकी नहीं बचा। दितचरय आज भी है कि अंग्रेजों के जमाने में बने पुल, रेलवे पुल और सड़कें आज भी सी-सी साला बाद मजबूत से पड़ती हैं, जबकि आजादी के बाद कई खासकर हाल के वर्षों में बनी कई परियोजनाएं उद्घाटन के हवालों के भीतर बिखरने लगती हैं। यह फकत तकनीकी की कमी से नहीं, नीयत की कमी से पैदा होता है। देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है, और इस सपने की नींव सड़कों, पुलों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचे पर ही टिकी है। लेकिन जब हर मानसून में करोड़ों की परियोजनाएं धंसती, बंती और ढहती नजर आती हैं, तो यह सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या रपतार और गुणवत्ता एक साथ चल भी पा रहे हैं। जवाब तक कमीशन की सूचनार्थ निर्माण की नींव से नहीं हटवाई जाएगी, तब तक हर नया एक्सप्रेसवे, हर नया पुल केवल एक नई सुर्खी बनकर रह जाएगा, जो पहली बारिश में ही उस प्रचटवार की गवाही देने लगेगा, जिस पर वह खड़ा किया गया है।

निलंबन और ब्लैकलिटिंग जैसी कार्रवाइयां देखने में सरख लगती हैं, लेकिन असर में रहकर कमजोर साबित होती हैं। जांच पूरी होने तक तीन इंचीमिटर के कगार से हटाना एक रस्म भर है, क्योंकि अगर चलकर वही अधिकारी किसी और परियोजना में लौट आते हैं। घटिया निर्माण के दांभी ठेकेदार भी काली सूची में डाले जाने के बाद नाया और कंपनी का घाटा बदलकर भाग सिर से टेडर बनने लगते हैं। यह खेत डलना पुराना और इतना संगठित हो चुका है कि अब इसे रोकने वाला कोई डर बाकी नहीं बचा। दितचरय आज भी है कि अंग्रेजों के जमाने में बने पुल, रेलवे पुल और सड़कें आज भी सी-सी साला बाद मजबूत से पड़ती हैं, जबकि आजादी के बाद कई खासकर हाल के वर्षों में बनी कई परियोजनाएं उद्घाटन के हवालों के भीतर बिखरने लगती हैं। यह फकत तकनीकी की कमी से नहीं, नीयत की कमी से पैदा होता है। देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है, और इस सपने की नींव सड़कों, पुलों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचे पर ही टिकी है। लेकिन जब हर मानसून में करोड़ों की परियोजनाएं धंसती, बंती और ढहती नजर आती हैं, तो यह सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या रपतार और गुणवत्ता एक साथ चल भी पा रहे हैं। जवाब तक कमीशन की सूचनार्थ निर्माण की नींव से नहीं हटवाई जाएगी, तब तक हर नया एक्सप्रेसवे, हर नया पुल केवल एक नई सुर्खी बनकर रह जाएगा, जो पहली बारिश में ही उस प्रचटवार की गवाही देने लगेगा, जिस पर वह खड़ा किया गया है।

बांकीपुर की जीत से बदलेगी सियासत की दिशा



वेद विलास उनियाल

उपचुनाव का यह नतीजा जहां बीजेपी को आत्ममंथन करने के लिए विवश करता है वहीं विपक्ष की बाढ़ी पार्टियों को भी यह अवसर नहीं देता कि इस जीत पर जश्न मना सकें। खासकर इस सीट पर जो आरजेडी जमानत नहीं बचा सकी उसके लिए भी विहार की सीमाओं में स्पष्ट संदेश है। एक राज्य का उपचुनाव का परिणाम किस तरह पूरे देश भर में अपनी धमक दिखा सकता है, इसे बिहार बांकीपुर चुनाव के नतीजे आने के बाद महसूस किया जा सकता है। इस एक सीट ने देश की सियासत के कई संदेश एक साथ दे दिए हैं। बांकीपुर की वह सीट, जिसमें कई कांग्रेस से बीजेपी के लिए चुनाव एक औपचारिक—सा माना जा रहा था वह उसके प्रत्याशी का लगभग 19 हजार वोटों से पीछे रह जाना उसकी चौकाया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन



का गढ़ मानी गई इस सीट पर जनसुधार पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। 1995 से बीजेपी यहां कोई चुनाव नहीं हारी थी। इस सीट को नवीन परिवार की सीट कहा जाता रहा है। पुरखी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी विधानसभा चुनाव में 238 में 233 सीटों पर जनमत जवाब करकर हासिए पर थी। ऐसे में उपचुनाव का यह नतीजा जहां बीजेपी को आत्ममंथन करने के लिए विवश करता है वहीं विपक्ष की बाढ़ी पार्टियों को भी यह अवसर नहीं देता कि इस जीत पर उल्लास मना सकें। खासकर इस सीट पर जो आरजेडी जमानत नहीं बचा सकी उसके लिए भी विहार की सीमाओं में स्पष्ट संदेश है।

वर्ष 2024 में लोकसभा में अयोध्या की सीट हारने के बाद बीजेपी

के लिए बांकीपुर विधानसभा की सीट हारना दूसरा सदमा है। इस चुनाव ने बताया है कि चुनावी रणनीति ठीक हो, मतदाताओं के बजाय संचाद से अपने मुँहों को रखा जाए तो बंद बस सकते हैं। कुछ महीनों में ही अगर मतदाताओं की सोच में इतना फर्क आया है तो फिर बीजेपी को आकलन करना होगा कि इस अवधि में ऐसे कौन से घटनाक्रम हुए जिनसे मतदाता का मन बिल्कुल बदल गया। बीजेपी ने नामांकन खल होने से पहले एकाएक अपनी पार्टी का उम्मीदवार बदला। इससे साथ ही भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सर्वांग में निराशा फैली। वहीं न कहीं ऐसे अवसर पर दिल्ली में छात्रों के आक्रोश से भी किसी हद तक माहौल बदला। बीजेपी की कार्यशैली के साथ साथ मुख्यमंत्री शहादत चौधरी के बयानों ने भी मतदाताओं को नाराज किया। बीजेपी के प्रभाव वाले वोट जनसुधार पार्टी को मिले बिना इस तरह की बड़ी जीत हासिल करना संभव नहीं था। प्रशांत किशोर को बीजेपी के मत भी मिले और आरजेडी के भी। साथ ही इस चुनाव ने इस धारणा को भी और सबल बना दिया कि राष्ट्रीय पार्टियों के तौर-तरीके और शैली में जनता कहीं किसी बदलाव की अपेक्षा कर रही है। फिर वह चाहे तमिलनाडु में विजय व्रतवति को सत्ता थमाना हो या फिर बांकीपुर की सीट उन प्रशांत किशोर को सौंपनी हो, जो अपना पहला चुनाव पागे का संकेत लेकर आया था। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई

सीट पर जीत कर बड़े नायक बन गए हों। लेकिन उनकी जीत ने सियासत की कई संभावनाओं को सामने रख दिया है। इसका संदेश बिहार किशोर पूरे देश के लिए है। प्रशांत किशोर ने राजनीति के मिजाज को बखूबी समझा। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से न तो वह विचलित हुए न हताश हुए। उन्होंने कोई अनर्गल बयान नहीं दिया। एसआईआर पर भी वह ज्यादा नहीं बोले। वह जिस तरह बांकीपुर के मतदाताओं के समक्ष गए उसकी शायद मतदाताओं ने ली। बीजेपी या आरजेडी से हताश हो रहे मतदाता ने प्रशांत किशोर को सबसे बेहतर रिश्ता मिला।

देश में कुछ उपचुनाव ऐसे भी हैं जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा को बदल दिया। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई थी। लेकिन दक्षिण भारत में उसे आधार मिला था। यही उसे कर्नाटक की लोकसभा एक सीट चिकमंगलूर डीवी चंद्रगौड़ा ने इस्तीफा देकर खाली की थी। इंदिरा गांधी ने यहीं से उपचुनाव लड़ा था। यह उपचुनाव के लिए जनता पार्टी ने जनता दल के कद्दावर नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटेल को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आरसी मोतिलाल ने जुड़ कर ही जनता पागे के लिए चिकमंगलूर का परिणाम पागे का संकेत लेकर आया था। उपचुनाव की बात करें तो पीछे संसदीय क्षेत्र में 1981 का चुनाव

—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं—

असम की बाढ़ और पर्यावरणीय क्षति



—नव लाकुरीया—

जैसे-जैसे पूर्वी असम में बाढ़ का पानी कम हो रहा है और सरकार हजारों प्रभावित परिवारों को फिर से बसाने की कोशिशें शुरू कर रही है, ध्यान धीरे-धीरे ऊपर की ओर आगे बढ़ाईयां पर जा रहा है। जुलाई 2026 के दूररेखे हिस्से में यहां हुई तैलाशा बारिश से असम के कई जिलोंजैसे शिवसारा, चराइदेव, गोलाघाट और जोराहाटकृमि भयावक आ बा गई। नालाईं और अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियां अपने साथ गाम और मिट्टी वाला पानी भरकर अलग पड़तीं। इससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि डूब गई, लाखों पालतू जानवर और भूमिगत जल स्रोतों से प्रदूषित पानी के कारण पशुओं की मृत्युएं हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के घर, फसलें और गांवों जानवर, धर्म, भूमिगत पानी के कारण हैं, पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि 18 से 22 जुलाई के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश और नालाईं में हुई भारी बारिश, जो 137 मिमी तक दर्ज की गई, इस आघात का दुर्घकारण थी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसांनों द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। पूर्वी असम की प्रमुख नदीजुकी जैसे दिवो, दिसांग, दारिका और जालीमूंमें अव्यवकास पानी और गंदगी का तेज बाढ़ फैला रहा है, बड़े बाढ़ नदी की क्षमता से कहीं अधिक भार और आधिकारिक जगहों पर तटबंध टूट गए। खबरों के मुताबिक, नालाईं सरकार ने दिसपुर प्रशासन को संभावित आघातों के बारे में तुरंत चेतावनी दी थी, लेकिन असम राज्य आया प्रबंधन प्रक्रियाएँ शायद स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाया। बचाव के लिए तत्काल कदम उठाने वाले प्रभावी अधिकारी चेतावनी दी की कमी और जिला प्रशासन, खासकर शिवसारा और चराइदेव, की तैयारी न होने से आपदा और भी विकराल हो गई।



यदि प्रशासन जनता के बजाय सत्ता के हितों की रक्षा करता दिखाई दे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्वसनीयता स्वतः समाप्त होने लगती है। पाकिस्तान की यही दोहरी नीति आज उदक लोकतांत्रिक दवाओं पर गंभीर प्रतिक्रिया खड़े करती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी बीज केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद एक का सामान्य नागरिक लभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बिजली संकट, नईगाई, शोराजिना और आवश्यक वस्तुओं की कमी और विकास की धीमी गति ने जनजीवन को अत्यंत कठिन बना दिया है। यह विडंबना है कि जिन नदियों को उज्ज्वल उपजन्म होती है, उसी क्षेत्र के लोग लंबे समय तक बिजली कटौती झेलने को विवश हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन उनसे विकास के लिए अपेक्षित निवेश नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में जनता के भीतर अस्तोता का बड़ेना जमाविक है।

लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी कसौटी यह होती है कि वह संकट के समय जनता के साथ किस प्रकार खड़ा रहता है। यदि जनता की शिकायतों का समाधान संवाद से करने के बजाय दमन से किया जाए, तो यह शासन का कानूनीरी का प्रमाण होता है। लोकतांत्रिक अधिकृत कश्मीर में विरोध 1 प्रदर्शनों और अस्तोता के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं, वे चिंता पैदा करते हैं। लोकतंत्र का उत्तर दिली नहीं, बल्कि संवाद होता है। दुर्भाग्य का अर्थ केवल चुनाव करवा देना नहीं है, बल्कि असहमति का समाधान करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और सत्ता की आलोचना को स्वीकार करना भी है। यदि विरोध करने वाली को राष्ट्रप्रेमिया या व्यवस्था विरोधी बताकर दबावे का प्रयास किया जाए, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाए और

नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और महाशक्तियां अनेक अवसरों पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों और लोकतंत्र में चुनौती का बल करती हैं। यदि यही सिद्धांत सार्वनीयक हैं, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उठ रहे प्रश्नों की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। मानवाधिकारों का मूल्य भीनातिक सीमाओं से निर्धारित नहीं होता। जहाँ भी नागरिकों की स्वतंत्रता और समान प्रभावित होता है, वहीं वैश्विक समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे। संघर्ष में हाल की घटनाओं के माध्यम में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति की ओर आकर्षित किया है और बाह्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा दमन रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस प्रकार की अपील को केवल कूटनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया पर लगातार प्रश्न उठ रहे हों, यदि नागरिक असुखा और अविश्वास के वातावरण में जी रहे हों और यदि उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों, तो विश्व समुदाय की निष्क्रियता निश्चय के लिए और भी गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती है। पाकिस्तान की लोकतांत्रिक नीतियों का सबसे बड़ा विश्लेषणमात्र यह है कि एक ओर वह अंतरराष्ट्रीय नों को लोकतंत्र, नाय और नागरिकों के बीच करता है, वहीं दूसरी ओर अपने निजंत्रण वाले देशों में उसी मूल्यों को व्यवहार में उतारने में विफल दिखाई देता है। भाषणों की विश्वसनीयता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली से सिद्ध होती है। यदि नागरिक स्वयं को उपेक्षित, असुरक्षित और अज्ञात महसूस करें, तो लोकतंत्र का दावा खोखला प्रतीत होने लगता है। लोकतांत्रिक वास्तविक अर्थ सत्ता परिवर्तन की संभावना, स्वतंत्र संस्था निर्माण और नागरिकों की गरिमा की रक्षा है। यदि ये तत्व अनुपस्थित हों तो चुनाव

केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हों। मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपने मतधिकार का प्रयोग कर सकें, राजनीतिक दल समान अवसर प्राप्त करें और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास पुनर्स्थापित हो। यह केवल उस क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं, बल्कि पूरी दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति के लिए भी आवश्यक है। विश्व की महाशक्तियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल वक्तव्यों से नहीं होती। जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं, वहाँ समय रहते निष्पक्ष निगरानी, संवाद और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए रचनात्मक प्रयास आवश्यक होते हैं। यदि दुनिया ऐसे मामलों में मौन रहती है, तो लोकतंत्र के सार्वनीयक मूल्यों की विश्वनीयता भी कमजोर पड़ती है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियाँ दुनिया के लिए एक चेतावनी हैं कि चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। यदि यह विश्वास टूट जाता है, तो अस्तोता, अविश्वास और संघर्ष की परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं। आज आवश्यकता किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र, नाय, पारदर्शिता और मानवाधिकारों की रक्षा करने की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निष्पक्ष दृष्टि से स्थिति का आकलन करने और वह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ के नागरिकों को वही अधिकार और समान मिले, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के नागरिकों के सामाविक अधिकार हैं। दुनिया की आँखें अब इस ओर खुलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ लोकतंत्र कमजोर होता है, वहाँ अंततः पूरी मानवता की नैतिक शक्ति भी कमजोर पड़ती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में हुई तबाही पर चिंता जताई और मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में असम के नेताओंकजिनमें केंद्रीय बजट, जहाजरानी और जलमय मंत्री रवीन्द्र सोनोवाल तथा राज्य भाषा अख्यक्ष दिलीप सिंहका शास्त्र केकृ के साथ बाकी की स्थिति की समीक्षा की। कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री हिमत बिस्वा सर्मा से फोन पर बात की और असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का संकेत दिया। गृह मंत्री मोदी ने भी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए सर्मा से बात की और राहत, बहाली तथा पुनर्निर्माण के कामों में हर जरूरी मदद का संकेत दिया। इस बीच, पूर्वी असम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने में आई छह सदस्यीय और—मंगलुरी केंद्रीय समीक्षा टीम ने अपना काम पूरा कर लिया है। टीम के सदस्यों को असम और नालाईं में मिले कुल हवातों में 100 बेलाहामी भारी बारिश से हुए बड़े नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। असम सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र से एक विशेष पैकेज की मांग की है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा, जिन्होंने पहले दिन से ही बचाव और राहत कार्यों की कमान संभाली थी, ने हाल ही में प्रभावित परिवारों के बाढ़ रक्षित उपकरणों की घोषणा की, जिसमें अपनों को खोने वालों के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद भी शामिल है। मुक्तकों के परिवारों को पहले घोषित भार लाख रुपयों की अनुमति राशि के अलावा अब पांच लाख रुपयों की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इससे अलावा, बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में लापता हुए लोगों, जो 30 दिनों से अधिक समय से लापता हैं, के परिवारों को भी भार लाख रुपयों की मदद मिलेगी। सर्मा ने यह भी कहा कि बाढ़ से प्रभावित एक लाख से अधिक परिवारों को उनकी जरूरी जरूरतें पूरी करने के लिए तत्काल 15,000 रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे। प्रभावित लोगों में रहने वाले अंग्रेजी योजना के लाभार्थियों और छात्रों को एकमुश्त आर्थिक मदद मिलेगी।

आज सखा हो जाऊँ कि जवाब ऐस सवालात का दे सखे हाजिर हो जाऊँ जबाबदेही लाया कीजनी और हमराव वही ताहिबो जो आपकें इन्जामार के लिये मुरारें है वारो इन्फिरसात कस्तरे मुकदमा के तजीबीज हुई हैं और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुजुमा दस्तावेजो जिनको आप अपना जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें। आपको इतनाही दी जाती है कि अगर बरोज जुजुमा को हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरोर हाजिर आपकें मसमूमो और फैसला होगा। बरसल हम देखलात ओ मुहर अदातल के आज बाराहीया माह सन 20 ई जौ किया गया।